उत्कर्ष 2029

मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा (2026-29)

भारतीय रिज़र्व बैंक

प्राक्कथन

"भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं।"

महात्मा गांधी

संस्कृत में उत्कर्ष का अर्थ है "उत्कृष्टता"। यह शब्द भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई, बैंक) के मूल तत्व और प्रकृति को साकार करता है। निःसंदेह, उत्कृष्टता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। चाहे महामारी की उथल-पुथल से निपटने के दौरान उत्कर्ष 2022 हो या महामारी के बाद की दुनिया के लिए वित्तीय क्षेत्र की पुनर्कल्पना करने के लिए उत्कर्ष 2.0 हो - उत्कर्ष ने जुलाई 2019 से आरबीआई के पथप्रदर्शक की भूमिका निभाई है।

उत्कर्ष 2029, वर्ष 2026 से 2029 के लिए आरबीआई की कार्यनीति रूपरेखा है और इसे संस्थागत उद्देश्य को कार्यक्षम उत्कृष्टता में रूपांतरित करने के लिए बनाया गया है। एक स्पष्ट परिदृष्टि कथन के साथ बैंक के स्थायी मूल्यों को आधार बनाते हुए, उत्कर्ष 2029 को छह कार्यनीति स्तंभों द्वारा सुदृढ़ किया गया है जो बैंक के विभिन्न कार्यों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार किए गए उनचास व्यापक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली डिलिवरेबल्स को समाहित करते हैं।

तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, निरंतर बदलती भू-राजनीतिक गतिकी और उभरती जलवायु संबंधी अनिवार्यता के दौर में, उत्कर्ष 2029, अन्य विषयों के साथ-साथ, विनियमनों को सरल बनाने, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, वित्तीय बाजारों की गहनता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कर्मचारियों को कार्य-कुशल बनाने आदि क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह भुगतान प्रणालियों की पहुंच का विस्तार और वैश्वीकरण करने, वित्तीय परितंत्र को मजबूत करने, आरबीआई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बेंचमार्क करने के लिए मजबूत मेट्रिक्स स्थापित करने और इस प्रकार आरबीआई को एक विश्व स्तरीय पूर्ण-सेवा युक्त केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास करता है।

उत्कर्ष 2029 केवल एक मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता के साथ जटिलता को पार करने और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के आरबीआई के संकल्प के लिए एक साझा दिशासूचक है। यह एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में सार्थक योगदान देने की सामूहिक आकांक्षा को सुदृढ़ करता है। जय हिन्द!

संजय मल्होत्रा
गवर्नर

30 मार्च 2026

कार्यकारी सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी पहली मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा, अर्थात् 'उत्कर्ष 2022', जुलाई 2019 में तैयार किया था, इसने वार्षिक कार्य योजनाओं, जो लघु अवधि के लिए बनाई जाती थीं और कार्यनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थीं, का स्थान लिया था। उत्कर्ष 2022 ने एक उद्देश्य कथन, छह परिदृष्टि कथन, 24 कार्यनीतियां, 153 लक्ष्य और दिसंबर 2022 तक हासिल किए जाने वाले 352 माइलस्टोनों को स्पष्ट किया था। उसके बाद की कार्यनीति रूपरेखा, अर्थात्, 'उत्कर्ष 2.0', 2023-25 की अवधि के लिए तैयार किया गया था। इसने, उत्कर्ष 2022 की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसके मूल उद्देश्य, मूल्यों और उद्देश्यों के साथ-साथ छह परिदृष्टि कथनों को बनाए रखा। उत्कर्ष 2.0 ने 170 माइलस्टोनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा।

पिछली दो रूपरेखाओं को जारी रखते हुए, उत्कर्ष 2029, वित्तीय वर्ष 2026-29 के तीन वर्ष की समय अवधि के लिए आरबीआई की मध्यम अवधि कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। यह शीर्ष से निम्न और निम्न से शीर्ष तक के दृष्टिकोणों का एक विचारपूर्वक मिश्रण है, जो आरबीआई की परिदृष्टि को हासिल करने के लिए आगामी डिलिवरेबल्स के साथ दूरदर्शी दृष्टिकोण को जोड़ता है। यद्यपि आरबीआई के नियमित कार्य जारी रहेंगे, उत्कर्ष 2029 के दायरे में लाए गए व्यापक और प्रभावशाली डिलीवरेबलों का लक्ष्य, जोखिमों का प्रबंधन करने, नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने, हितधारकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीयकरण पहलों का विस्तार करने के लिए कार्यों को उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है, जिससे यह एक भविष्योन्मुख संगठन बन जाएगा।

उत्कर्ष 2029 रूपरेखा में, आरबीआई की परिदृष्टि और मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होने के साथ-साथ भारत को विकसित भारत बनाने की व्यापक परिदृष्टि वाले कार्यनीति स्तंभ और डिलीवरेबलों हैं। छह कार्यनीति स्तंभ प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, प्रत्येक स्तंभ व्यापक, उद्देश्यपूर्ण, अग्रणी और रूपांतरक डिलीवरेबलों को समाहित करता है, जो बैंक के विभिन्न कार्यों के बीच अंतर्संबंध का भी ध्यान रखते हैं, जिससे सहयोगी तरीके से निर्धारित डिलीवरेबलों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इन डिलीवरेबलों की निगरानी, उत्कर्ष वेब एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी, इसके तहत शीर्ष प्रबंधन को त्रैमासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रगति की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। आवधिक निगरानी तंत्र, गतिशील परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि यह कार्यनीति रूपरेखा वित्तीय परितंत्र तंत्र की उभरती आवश्यकताओं के प्रति सजग है। इस कार्यनीति रूपरेखा को आरबीआई के वित्तीय वर्ष के साथ भी संरेखित किया जा रहा है, ताकि गतिविधि-आधारित बजटिंग के तहत संसाधन आवंटन को समन्वित किया जा सके, जिससे यह एक सुसंगत रूपरेखा बन जाएगी।

I. उत्कर्ष 2029 – 2026-29 के लिए मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा

प्रस्तावना

I.1 उत्कर्ष 2029 आरबीआई को एक विश्व स्तरीय पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसकी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। एक कार्यनीतिक रूपरेखा के रूप में, यह व्यापक और प्रभावशाली डिलिवरेबलों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि नियमित गतिविधियां इस रूपरेखा के बाहर जारी रहेंगी। अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक तीन वर्षों में, उत्कर्ष 2029 कुछ दीर्घकालिक डिलिवरेबलों को हासिल करने के लिए नींव भी रखता है जैसे कि मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट स-मुद्रा को लागू करना, सीमा पार भुगतान को कार्यदक्ष बनाने के लिए सीबीडीसी का विस्तार करना, समावेशी ऋण वितरण के लिए यूएलआई का विस्तार करना, हमारे वित्तीय क्षेत्र में एआई और क्वांटम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए रूपरेखा विकसित करना, इत्यादि। साथ ही, उत्कर्ष 2029 उन दीर्घकालिक डिलिवरेबलों को जारी रखेगा जिनके लिए उत्कर्ष 2.0 के तहत नींव रखी गई थी, जैसे कि सीमा पार भुगतान में क्रांति लाने के लिए आईएनआर के साथ-साथ यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण आदि। उत्कर्ष 2029, अप्रैल से मार्च तक आरबीआई के वित्त वर्ष के साथ स्वयं को संरेखित कर रहा है, जिससे गतिविधि-आधारित बजटिंग के माध्यम से संसाधनों के आवंटन और उपयोग का समन्वय सुनिश्चित होता है। ।

संरचना

I.2 उत्कर्ष 2029 को तीन-स्तरीय संरचना में ठीक से समायोजित किया गया है जिसमें कार्यनीति स्तंभ शामिल हैं, प्रत्येक स्तंभ में डिलिवरेबलों का एक सेट शामिल है, जो आरबीआई के परिदृष्टि और मूल्यों द्वारा निर्देशित है (चार्ट I.1)

चार्ट I.1: उत्कर्ष 2029 की संरचना

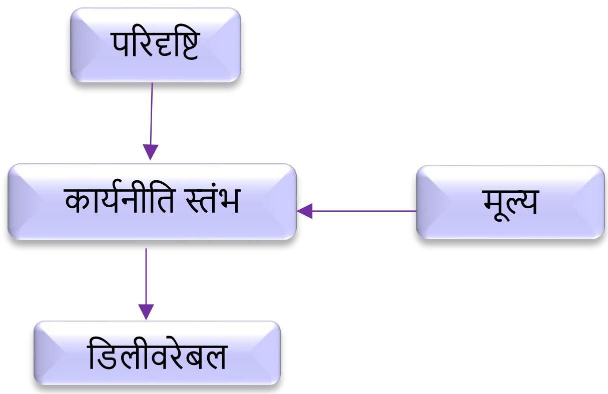

परिदृष्टि और मूल्य

I.3 उत्कर्ष 2029 का परिदृष्टि कथन पिछले उत्कर्ष संस्करणों के उद्देश्य, परिदृष्टि और मूल प्रयोजनों को परिष्कृत करता है:

'एक स्थिर, समावेशी और प्रौद्योगिकी रूप से सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को सक्षम करते हुए उत्कृष्टता जारी रखना।'

I.4 उत्कर्ष 2029 आरबीआई के कार्यों को मार्गदर्शित करने के लिए उत्कर्ष 2022 और उत्कर्ष 2.0 के मूल्यों का अनुसरण करता है:

सारणी I.1: आरबीआई के मूल्य और कार्य

मूल्य	कार्य
सार्वजनिक हित	ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करके सार्वजनिक हित सुनिश्चित करना
सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता	सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखकर विश्वास को बढ़ावा देना
प्रतिक्रियाशीलता और नवाचार	वित्तीय परितंत्र की बदलती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के प्रति कुशल और प्रतिक्रियाशील बने रहना
विविधता और समावेशिता	अपनी सभी गतिविधियों में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना
आत्म-निरीक्षण और उत्कृष्टता का अनुसरण	पेशेवर उत्कृष्टता पाने की कोशिश करना और निरंतर आत्म-मूल्यांकन के प्रति प्रतिबद्ध रहना

कार्यनीति स्तंभ और डिलीवरेबल

I.5 मूल्य प्रदान करने के लिए, प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों, निर्देशों को सरल बनाने, संप्रेषण में स्पष्टता लाने, अनुपालन लागत को कम करने और हितधारक केंद्रितता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। उत्कर्ष 2029 में उच्च-प्रभावी परियोजनाएं भी शामिल हैं, हालांकि उन्हें हासिल करने की समय सीमा तीन वर्ष से अधिक हो सकती है, फिर भी इस अवधि के दौरान मजबूत आधार तैयार किया जाएगा। इसे कार्यनीति स्तंभों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जो बैंक के लिए कार्रवाई योग्य मदों को कार्यनीतिक प्राथमिकताओं और उन डिलीवरेबलों के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं।

I.6 आंतरिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई के सभी केंद्रीय कार्यालय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय और सहायक संस्थाओं से प्राप्त निविष्टियों को, जहां लागू हो, डिलीवरेबलों के मूर्त रूप देने हेतु शामिल किया गया है। समय सीमा स्थापित करते समय आंतरिक / बाहरी हितधारकों से आवश्यक अंतर्संबंध, अंतर्निर्भरता और समर्थन को ध्यान में रखा गया है। आरबीआई@100 के लिए आकांक्षी लक्ष्यों

और विकसित भारत 2047 और पंच प्रण के तहत सरकार के साथ साझा किए गए लक्ष्यों से भी मार्गदर्शन लिया गया है। छह कार्यनीति स्तंभों के तहत 49 डिलीवरेबलों, उत्कर्ष 2029 रूपरेखा को समाहित करते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्यनीति स्तंभ आरबीआई की एक अलग और महत्वपूर्ण प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है।

उत्कर्ष 2029 के कार्यनीति स्तंभ और उनके केंद्रित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

सारणी I.2: कार्यनीति स्तंभ

कार्यनीति स्तंभ	विवरण	फोकस क्षेत्र
1	सुदृढ़ विनियमन	सरलीकरण, आघातसह
2	ग्राहक केंद्रितता और समावेशी वित्त	सुलभता, अंतर्संबंध
3	प्रतिस्पर्धी बाजार	वित्तीय गहनता, डिजिटलीकरण
4	प्रभावी प्रौद्योगिकी	नवाचार, साइबर सुरक्षा
5	भविष्य के लिए तैयार संगठन	कौशल विकास, वहनीयता
6	वैश्विक भारत	मानकीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण

I.7 **सुदृढ़ विनियमन** – आरबीआई नियमित रूप से निर्देशों की समीक्षा, तर्कसंगत बनाने और सरलीकरण करने का प्रयास करता है, ताकि इसके विनियमनों / मास्टर दिशानिर्देशों / मास्टर परिपत्रों को बदलती आर्थिक गतिशीलता के साथ संरेखित किया जा सके और विनियमित इकाइयों के लिए अनुपालन बोझ को कम किया जा सके, जिससे व्यवसाय करने में आसानी बढ़े। बैंक का उद्देश्य प्रक्रियात्मक अतिरेक को कम करना, विनियमित इकाइयों को अधिक संचालन लचीलापन प्रदान करना, वित्तीय प्रणाली के वर्तमान और उभरते क्षेत्रों में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

I.8 **ग्राहक केंद्रितता और समावेशी वित्त** – बैंक, वित्तीय प्रणाली के भीतर अंतिम चरण तक सुलभता और समावेशन सुनिश्चित करने में बहुमुखी भूमिका निभाता है। शिकायत निपटान में तीव्रता लाने और ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए बैंक ने एससीबी में ग्राहक सेवा का आकलन करने और सभी विनियमित इकाइयों में शिकायत को आगे बढ़ाने संबंधी रूपरेखा तैयार की है। यूएलआई को बढ़ाकर, बैंक ने वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने, ऋण लागत को कम करने और समावेशी ऋण वितरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय प्रणाली में अंतर्संबंध पर जोर देते हुए, बैंक प्रणाली-व्यापी संक्रमण जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा और बढ़ावा देने का विचार रखता है। नागरिकों चार्टर के तहत सेवाओं के वितरण की समीक्षा करके और उस पर आवधिक मेट्रिक्स प्रकाशित करके, आरबीआई अपने निरंतर आत्म-मूल्यांकन और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

I.9 **प्रतिस्पर्धी बाजार** – यह कार्यनीति स्तंभ अपने दायरे के तहत बाजारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करके बाजार बुनियादी संरचना को मजबूत करने, बेहतर परिचालन दक्षता

के लिए केंद्रीय समाशोधन में वृद्धि करने, जोखिम को कम करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यह स्तंभ उन डिलीवरेबलों पर केंद्रित है जिनका उद्देश्य बोली के समय को कम करना, सरकारी प्रतिभूति बाजार में मूल्य निर्धारण पारदर्शिता को मजबूत करना और खुदरा बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।

I.10 **प्रभावी प्रौद्योगिकी** – बैंक अपने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विनियमित इकाइयों और नागरिकों के साथ इंटरफेस को इलेक्ट्रॉनिक बनाना और कागज और / या ईमेल-आधारित संवाद को समाप्त करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। इसके अलावा, सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को अंत से अंत तक डिजीटल किया जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्राहक शिकायत निवारण से संबंधित परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस संबंध में कार्य ने पहले ही गति प्राप्त कर ली है। मैनुअल प्रक्रियाओं और भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल करने के लिए मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल को संवर्धित किया जा रहा है। बैंक के सभी कार्यप्रवाहों और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए इसी तरह की पहल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी आधारित पर्यवेक्षी उपकरणों को स्थापित करने, उद्देश्य-निर्मित एलएलएम पर आधारित एक स्वदेशी एआई उपकरण विकसित करने, ई-कुबेर 3.0 जैसे महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों को संवर्धित करने और मुद्रा आधारभूत संरचना और बैंकनोट में नवीनतम तकनीक को शामिल करने जैसी पहलें जारी रहेंगी। साइबर-जोखिम क्षमता निर्माण के माध्यम से, वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग, आस्ति टोकनीकरण का विस्तार, डिजिटल तथा एआई सैंडबॉक्स स्थापित करना पर एक रूपरेखा जारी करने आदि के संबंध में बैंक का लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार नवाचार और विचारशील उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही, बैंक की आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करता है और केंद्रीकृत संस्थागत स्मृति सृजित करता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।

I.11 **भविष्य के लिए तैयार संगठन** – एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक होने के नाते, बैंक एक बहुआयामी वातावरण में कार्य कर रहा है, जो संसाधनों के निरंतर कौशल विकास, अपने कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा, अपने हितधारकों के साथ दो-तरफा संचार को मजबूत करने और संस्थागत उत्कृष्टता में वृद्धि के लिए अपने कार्यों और निर्णयों में स्थिरता और जलवायु जागरूकता को शामिल करने के माध्यम से एक भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

I.12 **वैश्विक भारत** – बैंक, आधारभूत भुगतान संरचना को आधुनिक बनाने के लिए अन्य देशों में यूपीआई स्टैक के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर, आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान को बढ़ाकर, सीमा पार सीबीडीसी व्यवस्था का विस्तार करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों को अपनाकर शेष विश्व के साथ अधिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, इसका उद्देश्य सक्रिय रूप से नेतृत्व की भूमिका का अनुसरण करना है जो भारत, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विमर्शों में निभा सकता है।

I.13 उत्कर्ष 2029 के तहत, क्षेत्रीय कार्यालय, जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यमों के रूप में काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण और अंतिम चरण तक की सेवा क्षेत्रीय वास्तविकताओं में प्रदर्शित हों। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आरबीआई का विविधता और समावेशिता का मूल्य इसके कार्यनीतिक रचना में अंतर्निहित है।

I.14 उत्कर्ष 2029 का शुभारंभ उस महत्वपूर्ण क्षण में हो रहा है जब भारत, अपने जी20 विरासत और वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्षता का लाभ उठाकर बहुपक्षीय और दक्षिण-दक्षिण वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। यह कार्यनीति संरचना भारतीय रुपये के वैश्विक एकीकरण को आगे बढ़ाने, यूपीआई को अन्य देशों तक विस्तारित करने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सीबीडीसी व्यवस्थाओं का विस्तार करने के रोडमैप का एक अभिन्न अंग है। उत्कर्ष 2029 केवल एक कार्यनीतिक संरचना नहीं है बल्कि आरबीआई के मूल्यों के दृढ़ पालन, व्यवस्थित लचीलापन पर अटूट ध्यान और सार्वजनिक सेवा के प्रति अथक प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने के उत्साह की पुन: पुष्टि है। आरबीआई अनुशासित निष्पादन, निरंतर आत्मनिरीक्षण, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और अपने सभी हितधारकों को लाभान्वित करने वाले परिणामों हेतु केंद्रित समर्पण के माध्यम से इस रोडमैप को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा।

****

चुनिंदा संक्षेपाक्षर

एआई	-	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
सीबीडीसी	-	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
आईएनआर	-	भारतीय रुपया (₹)
एलएलएम	-	बड़ा भाषा मॉडल
आरबीआई	-	भारतीय रिज़र्व बैंक
एससीबी	-	निर्धारित वाणिज्यिक बैंक
यूएलआई	-	एकीकृत ऋण इंटरफेस
यूपीआई	-	एकीकृत भुगतान इंटरफेस

भारतीय रिज़र्व बैंक
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग